भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4056
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नगरीय क्षेत्रों में चुनौतियों का आकलन

†4056. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नगरीय क्षेत्रों में आने वाली वर्तमान चुनौतियों जैसे तेजी से हो रहे शहरीकरण, जलवायु संबंधी खतरों, बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता और असमानताओं पर कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके प्राथमिक निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय सरकारों को 74वें संविधान संशोधन के तहत कार्यों के सीमित हस्तांतरण में देखी गई नगरीय नियोजन में स्थानीय स्वामित्व और निर्णय लेने की कमी सहित नगरीय शासन के मुद्दों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भौगोलिक और भू-आकृति स्थितियों के आधार पर शहरीकरण की चुनौतियाँ राज्य दर राज्य और शहर दर शहर अलग-अलग होती हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेप/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने विनियमित और नियोजित विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने के लिए शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 ([https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFA%20Guidelines%20Vol%20I\(2\).pdf](https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFA%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)) जारी किए हैं। शहरी शासन सहित शासन के मुद्दे को यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों

(योजना निर्माण और शहरी नियोजन दृष्टिकोण पर अध्याय) में शामिल किया गया है। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2014 का अध्याय - 6 "स्थिरता दिशानिर्देश" जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, पर्यावरण नीतियों, आपदा प्रबंधन आयोजना आदि सहित शहरी विकास के पहलुओं और स्थिरता से संबंधित है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न योजनाओं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) और आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)के माध्यम से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने/संवर्धित करने में राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

शहरी नियोजन सुधारों को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की हैं:

i. पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23 - भाग VI (शहरी नियोजन सुधार) - सुधार घटकों में विरोधाभासों को दूर करके और भूमि उपयोग को इष्टतम करके भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) जैसे आधुनिक शहरी नियोजन तरीकों को अपनाना, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) का कार्यान्वयन, पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अलावा राज्यों को स्पॉन्ज शहरों के निर्माण, सार्वजनिक परिवहन हेतु बसें चलाने के लिए कर हटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

ii. पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 - भाग III (शहरी नियोजन सुधार) - सुधार घटकों में योग्य शहरी योजनाकारों को नियुक्त करके मानव संसाधनों में वृद्धि, नगर नियोजन योजना (टीपीएस)/भूमि पूलिंग योजना का कार्यान्वयन, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, किफायती आवास और स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास को बढ़ावा देना, पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी), नियोजन के तरीकों के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकार, शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, जलक्षेत्रों का विकास आदि शामिल हैं।